गृह मंत्रालय

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता मेंएक उच्चस्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए कईआपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के disaster resilient India के विज़न को साकार करने के लिये गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने हेतु अनेक पहलें की गयी हैं

उच्चस्तरीय समिति ने मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 2514.36 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी

उच्चस्तरीय समिति ने असम, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए “राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण” योजना के तहत 810.64 करोड़ रुपये के खर्च वाले तीन परियोजना प्रस्तावों को भी मंजूरी दी

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लिए 150 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर GLOF जोखिम शमन के लिए एक परियोजना प्रस्ताव को भी उच्चस्तरीय समिति ने मंजूरी दी

उच्चस्तरीय समिति ने 470.50 करोड़ रुपये की लागत से युवा आपदा मित्र योजना (YAMS) को भी मंजूरी दी, इसे देश के 315 सबसे अधिक आपदा-संभावित जिलों में मास्टर ट्रेनर के रूप में 1300 प्रशिक्षित आपदा मित्र वॉलंटियर्स और 2.37 लाख वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करने

प्रविष्टि तिथि: 25 JUL 2024 8:13PM by PIB Delhi

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए कई आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय समिति की बैठक मेंवित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल हुए। समिति ने 6 शहरों में शहरी बाढ़ से निपटने, 4 पहाड़ी राज्यों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बाढ़ (GLOF) को कम करने और 3 राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से फंडिंग के कुल 9 प्रस्तावों पर विचार किया। समिति ने सभी 28 राज्यों में युवा आपदा मित्र योजना को लागू करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के disaster resilient Indiaके विज़न को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं। भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान-माल को होने वाले बड़े नुकसान को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

आज हुई बैठक में उच्चस्तरीय समिति ने तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के 6 महानगरों - मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे - में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 2514.36 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इससे पहले27 नवंबर 2023 कोउच्चस्तरीय समिति ने तमिलनाडु राज्य के लिए चेन्नई में 561.29 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ प्रबंधन के लिए एकीकृत समाधान वाले परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

उच्चस्तरीय समिति ने असम, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण" योजना के तहत 810.64 करोड़ रुपये के कुल खर्च वाले तीन परियोजना प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। केन्द्र सरकार ने इस योजना के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत

कुल 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और 11 राज्यों के1691.43 करोड़ रुपये केखर्च वाले प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी थी।

इसके साथ, उच्चस्तरीय समिति ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए 150 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर GLOFजोखिम शमन के लिए एक परियोजना प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। GLOFजोखिम शमन परियोजना इन चार राज्यों को GLOFजोखिमों से निपटने के लिए आवश्यक शमन उपाय करने में आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

उच्चस्तरीयसमिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से 470.50 करोड़ रुपये की लागत से युवा आपदा मित्र योजना (YAMS) के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसे देश के 315 सबसे अधिक आपदा-संभावित जिलों में मास्टर ट्रेनर के रूप में 1300 प्रशिक्षित आपदा मित्र वॉलंटियर्स और विशेष रूप से NCC, NSS, NYKS और BS&G (भारत स्काउट्स एंड गाइड्स) से लिए गए 2.37 लाख वॉलंटियर्स को आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया में प्रशिक्षित करने के लिए लागू किया जाएगा। यह कदम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विज़न के अनुरूप है जिसके तहत किसी भी आपदा के दौरान समुदाय को first responders के रूप में तैयार करने पर ज़ोर दिया गया है। इससे पहले सरकार द्वारा लागू की गई "आपदा मित्र" योजना के तहत देश के 350 सबसे अधिक आपदा-संभावित जिलों में आपदा प्रतिक्रिया के लिए लगभग 1 लाख सामुदायिक वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया है। ये कुशल और प्रशिक्षित 'आपदा मित्र' और 'आपदा सखियाँ' किसी भी आपदा से निपटने में स्थानीय प्रशासन की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

केन्द्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरानराज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत 14 राज्यों को 6348 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) के तहत 6 राज्यों को 672 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत 10 राज्यों को 4265करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

*****

आरके / वीवी / आरआर / पीआर

(रिलीज़ आईडी: 2037166) आगंतुक पटल : 319

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Hindi_MP , Assamese , Gujarati , Tamil , Telugu , Kannada